[Mr. Deputy Speaker]

you can raise it after he has moved the bill. He has to move the bill. Only after he has moved it, can there be a point of order. There can be no point or order. (*Interruptions*)

There is no point of order. Please take your seat. There is no point; there is no business unless he moves the Bill. You cannot have your say in a vacuum.

(*Interruptions*)

श्री नाथू सिंह : मंत्री महोदय जा रहे हैं। इन को आप रोकें । मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have your point of order after he moves the Bill. You move the Bill.

(*Interruptions*)

श्री नाथू सिंह : उन्होंने कहा है कि नेपाल सरकार से बात चल रही है । बात करने से कुछ नहीं होगा । बाढ़ की भयंकर समस्या है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Calling attention is over. Please take your seat. Just because you want to have your say, You get up and say that you have a point of order. This is not the way to conduct yourself. Please take your seat.

(*Interruptions*)

श्री नाथू सिंह : आपने कालिंग अटेंशन स्वीकार किया है तो. . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will not allow the Lok Sabha to turn into a fish market. Please understand this. Mr. Patwary, please take your seat.

16·07 hrs.

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): I beg to move :

"That the Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, be taken into consideration."

महोदय यह बिल बहुत सीमित उद्देश्य से लाया जा रहा है । जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज आर्डर (एमैंडमेंट) एक्ट 1976 के लागू होने से गुजरात में मोची जाति जो पहले डांग और बलसार जिले की एक ही तहसील में अनुसूचित जाति थी इस बिल के लागू हो जाने से पूरे राज्य में मोची जाति अनुसूचित जाति बन गई है । ऐसा होने से वहां आन्दोलन उठ खड़ा हुआ आन्दोलन इस बात को लेकर हुआ कि डांग जिले और बलसार जिले की एक तहसील में जहां यह मोची जाति पहले से अनुसूचित जाति थी पूरे राज्य में अनुसूचित जाति बन गई । लोगों का इस से विरोध हुआ । विरोध इस कारण से हुआ कि इन दो इन स्थानों को छोड़कर बाकी जगहों पर मोची जाति के लोग उन अयोग्यताओं से पीड़ित नहीं हैं जो अस्पृश्यता से पैदा होती हैं । दूसरे जिला में इस जाति के लोग कम्पेरेटिवली ऐडवांस्ड हैं । डांग जिले और बलसार जिले की एक तहसील को छोड़कर जो दूसरे जिले हैं गुजरात के उन में जब यह जाति अनुसूचित जाति बन गई एरिया रस्ट्रिकशन रिमूवल एक्ट के अनुसार तो इस के विरोध में आन्दोलन खड़ा हो गया और आन्दोलन इसलिए खड़ा

हुआ कि --उन लोगों का यह कहना था कि यह जाति दो जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में अस्पृश्य नहीं है, अनटचबल नहीं है न पहले कभी थी और न आज हैं । इसलिए अस्पृश्यता से जो अयोग्यता पैदा हो गई हैं डिसएबिलिटीज पैदा होती हैं वे इन पर लागू नहीं होती । इसलिए यह जाति अन्य जिलों में पहले से ही औरों के मुकाबले में अधिक तरक्की किए हुए हैं एडवांस्ड हैं । इसलिए जब यह अनुसूचित जाति बन गई तो यह खतरा पैदा हो गया कि मोची जाति के लोग जो पहले अनुसूचित इन जिलों में थे और इन को जो सुविधायें मिल रही थीं वे सुविधायें बड़े पैमाने पर बंट जाएंगी जिससे उन को नुकसान होगा । राज्य सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया । और राज्य सरकार ने यह अनुशंसा की केन्द्रीय सरकार से कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए । एरिया रेस्ट्रिक्शन्स रिमूवल ऐक्ट से जो इस जाति के लोग पूरे राज्य में अनुसूचित जाति बन गये हैं उन को फिर से पहले की स्थिति में ला देना चाहते हैं जो स्थिति इस कानून के बनने के पहले थी । कौन कानून ? शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर अमेंडमेंट ऐक्ट, 1976 के पहले जो स्थिति थी उसी को फिर से ला दिया जाय, ऐसी राज्य सरकार ने अनुशंसा की हैं । और इस में बहुत दम है राज्य सरकार के कहने में, और इसलिये यह विधेयक लाया गया है । खाली गुजरात के लिये । और एक दो और बातें हैं जिनका मैं उल्लेख करूंगा । इसलिए यह बिल लाया गया है कि जो स्थिति पहले थी शेड्यूल्ड कास्ट्स शेडयूल्ड ट्राइब्स आर्डर अमेंडमेंट ऐक्ट, 1976 के पहले को जो स्थिति थी गुजरात में इस जाति के मामले में, सिर्फ मोची जाति के मामले में, वही स्थिति फिर से ला दी जाए । ऐसा होने से मोची जाति के लोग सिर्फ डांग और बलसर जिले में अंबरगांव ताल्लुका में अनुसूचित जाति के होंगे और स्थानों में नहीं होंगे ।

16.11 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair*]

इस के अतिरिक्त जो कुछ अशुद्धियां थीं पंक्चुएशन की शैड्यूल्ड कास्ट्स शैड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर अमेंडमेंट ऐक्ट; 1976 में उन को भी इस में ठीक करने का उपबन्ध किया गया है । यह बहुत साधारण सी बात है । दूसरी चीजों में जो उपबन्ध किया गया है वह है कि कर्नाटक में ऐंट्री 63 में जो शब्द हैं "वणकर मारुवणकर" इसमें वणकर के आगे कौमा लगा दिया जाय यानी "वणकर मारुवणकर" । ऐसे ही ऐंट्री 75 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् "75. मश्ती" । ऐसे ही आन्ध्र प्रदेश में ऐंट्री 20 में शब्द "मेदकनलगौंड" के स्थान पर "मेदक नलगौन्ड" रखे जायें । ऐसे ही असम में औटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में ऐंट्री 14 में यह शब्द जोड़ने के लिये कहा गया है "सिन्तेग" । ऐसे ही महाराष्ट्र में ऐंट्री 18 में "गौंड राजगौंड" के स्थान पर "गौंड" के आगे कौमा लगाकर "गौंड, राजगौंड" सबस्टीट्यूट करने के लिये कहा गया है ।

तो इस तरह से महोदय एक तो गुजरात में शैड्यूल्ड कास्ट्स शैड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर अमेंडमेंट एक्ट, 1976 के पहले की जो स्थिति थी मोची जाति के सम्बन्ध में उसी स्थिति को फिर से कायम करने के लिये उपबन्ध किया गया है । और दूसरी कुछ जगहों पर जहां उस आर्डर के पंक्चुएशन में जो भूल हो गई थी, उसमें उसको शुद्ध कर लिया गया है और उसी के लिये उपबन्ध किया गया है । इस आबादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सीट पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । इसलिये हमने उसके लिये कोई उपबन्ध नहीं किया है ।

[Shri Dhanik Lal Mandal]

यह बहुत छोटा सा, सीमित उद्देश्य वाला बिल है, इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह इससे सहमत हो जायें ।

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain Castes and tribes, be taken into consideration."

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : (Ratnagiri) : In entry No. 18 Government is making an amendment as far as Maharashtra is concerned. I would like to know whether Gonda and Rajgonda according to Government are two different castes or is one caste.

MR. CHAIRMAN : I would request the hon. member that he can raise this point in the course of his speech. I do not think it is a proper stage to raise now.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) : There is a Commission for the Scheduled Cases and the Scheduled Tribes. There is also a Committee for the Welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tbibes. I would like to know from the Minister whether this Parliamentary Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes or the Commission, whatever they may be, do they submit any report to the Government asking to delete these castes ?

MR. CHAIRMAN : I think that can also be put at a later stage and not now.

Now I take up amendments to be moved.

The movers of amendments Nos. 3, 6, 15 and 16 are not here.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormngao) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1978." (23)

SHRI DURGA CHAND (KANGRA) : I beg to move :

"That the Bill to provide for the inclusion in and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, be referred to a Select Committee consisting of 8 members, namely :—

Dr. Baldev Prakash, Shri Baldev Singh Jasrotia, Shri Mukhtiar Singh Malik, Shri Dhanik Lal Mandal, Shri Nathu Singh, Shri Y. P. Shastri, Shri Ugrasen ; and Shri Yuvraj

with instructions to report by the first day of the next Session." (42).

SHRI SURAJ BHAN(Ambala) : I beg to move :

"That the Bill to provide for the inclusion in. and the exclusion from. the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. of certain castes and tribes, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 15 members, 10 from this House, namely :—

Shri Bharat Singh Chowhan, Shri Morarji R. Desai, Shri Hukam Chand Kachwai, Shri R. L. Kureel, Shri Dhanik Lal Mandal, Shri Kusuma Krishna Murthy, Shri Nathuni Ram, Shri Ram Dhan, Shri Shiv Narain Sarsonia, Shri Suraj Bhan; and 5 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee.

that the Committee shall also be instructed to examine the lists contained in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 and to suggest amendments thereto in their report;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the next session;

that in other respect the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha to join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 5 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee." (45)

SHRI CHHABIRAM ARGAL (Morena) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th April, 1979." (48)

"That the Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, be referred to a Joint Committee of the House consisting of 15 members, 10 from this House, namely :-

Shri Subhash Ahuja, Shri Shyamlal Dhurve, Shri S. S. Lal, Shri Raghubir Singh Machhand, Shri Dhanik Lal Mandal, Dr. Laxminarayan Pandeya, Shri Raghav-Ji, Shri Ram Charan, Shri Suraj Bhan, Shri Chhabiram Argal ,

and 5 from Rajya Sabha ;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one third of the total number of members of the Joint Committee ;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session ;

that in other respect the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variation and modifications as the Speaker may make ; and

that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 5 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee." (49)

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Ambalapuram) ; I beg to move :

"That the Billl be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st December, 1978." (53)

"That the Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, be referred to a Joint Committee of the House consisting of 23 members, 15 from this House namely :—

Shri Balak Ram, Shri Chand Ram, Shri Bharat Singh Chowhan, Shri Hukam Chand Kachwai, Shri B. C. Kamble, Shri R. L. Kureel, Shri Dhanik Lal Mandal, Shri Nathuni Ram, Shri Ram Dhan, Shrimati B. Radhabai Ananda Rao, Shri Shiv Narain Sarsonia, Shri Sheo Narain, Shri Suraj Bhan, Shri Bhausahab Thorat, Shri V. Tulsiram,

and 8 from Rajya Sabha ;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall also be instructed to examine the list contained in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 and to suggest amendments thereto in their report;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 8 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee." (54)

MR. CHAIRMAN : The amendments are also before the House.

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY I would like to express my views on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1978.

In my notice I have specifically stated that the Bill may be circulated for eliciting public opinion because this is only the Bill which has received a number of notices either to delete from or to include in different types of castes of this Schedule.

In our Constitution certain castes were included in the schedule and made it a schedule of castes. It clearly emphasises the fact that whenever a particular caste is to be included in or deleted from this schedule, the Government have a Constitutional responsibility to refer it to the States and ascertain their veiws. The main criterion taken into consideration by the founding fathers of the Constitution to include a caste in the Schedule was social disability. There is a basic difference between social problem and economic problem. As the minister has specifically stated, untouchability was one of the main criteria based on which the list was prepared and put into the schedule. But in due course, as we have seen from our experience in a number of States, different advanced communities also wanted to get themselves included in the schedule to have the advantages specifically guaranteed by the Constitution to these Scheduled Castes. We know that even some very well advanced communities try to get themselves included in these lists. In fact, this amounts to absolute mockery. It is a clear paradox that on the one hand

[Shri Kusuma Krishna Murthy]

they hate communities for their social disabilities and on the other hand, they try to get the advantages and preferences earmarked for those communities. Therefore, this matter cannot be considered in a haphazard manner. Many hon. members have given notices of amendments and I have also given a notice for an amendment specifically requesting that this Bill may be referred to a Joint Committee consisting of members from both Houses, so that the committee can go round the various States, meet the concerned people and discuss the matter and elicit their opinion. Based on those opinions, the question of inclusion or deletion of a particular community in the schedule can be taken into consideration. This is the proper appraoch, particularly because this is a very important Bill concerning about more than 22 crores of people in this country. If this is done in a haphazard way, without giving proper opportunity to the cross-section of these people in various States to express their opinion. I am sure. it will jeopardise the interests of these communities. This is my clear view and therefore I strongly plead, and request the hon. Minister to accept my amendment.

श्री दुर्गा चन्द (कांगड़ा) : सभापति महोदय, मैंने इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के बारे में अपनी एमेंडमेंट दी है । यह विधेयक महज एक स्टेट, गुजरात, में मोची कम्युनिटी के बारे में एमेंडमेंट करने के लिए लाया गया है। शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज (एमेंडमेंट) आर्डर एक्ट, 1950 के मुताबिक गुजरात में मोची कम्युनिटी की जो पोजीशन थी, उस को शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ (एमेंडमेंट) आर्डर एक्ट, 1976 के द्वारा बदल दिया गया था। उसको ठीक करने के लिए यह बिल लाया गया है।

पिछले नवम्बर सेशन में शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की 1970–71, 1971–72 और 1972–73 की रिपोर्ट्स के बारे में मेरी स्पीच के कुछ एक्स्ट्रेक्ट होम मिनिस्ट्री ने निकाले थे और बाद में उन के बारे में यह कमेन्ट्स दिये गये :

can be considered at the time of undertaking legislation for a comprehensive revision of the lists of scheduled castes and scheduled tribes in due course."

मैं कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का मसला बहुत बड़ा है । मैं समझता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज (एमेंडमेंट) आर्डर एक्ट, 1976 में भी बहुत खामियां हैं। और कई कम्युनिटीज जो हैं वह रह गई हैं। कइयों की ऐडीशन कर दी गई हैं। मैं समझता हूं कि काम्प्रीहेंसिव तरीके से जैसी लिस्टें बननी चाहिए थीं शेड्यूल्ड कास्ट की और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की उसमें बहुत खामियां हैं और खास कर पिछले सेशन में जब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पेश हुई थी, उस में जो बहस हुई थी उस बहस में बीसियों बातें मैं लाया था। तो जब तक कि काम्प्रीहेंसिव बिल न बने तब तक यह एक अमेंडमेंट लाने से मैं समझता हूं कि मसला हल नहीं होगा। यह पहला बिल है जिसमें पचास आदमियों ने अमेंडमेंट दिए हैं। इतने अमेंडमेंट जिस कानून में सदन के मेम्बरान की तरफ से आए हों उस कानून को इस तरीके से पास करने से मसला हल नहीं होगा । कई कम्युनिटीज इंतजार कर रही थीं कि कुछ दिनों के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आएगी तो काम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट बिल लाएगी जिस में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की ग्रीवांसेज को दूर किया जायेगा। तो मैं समझता हूं कि इस को सेलेक्ट कमेटी के पास रेफर होना चाहिए ताकि फिर रिवाइज्ड लिस्टें बनाई जायं जिस में कि अपने सारे भाई अपने विचार रख सकें और जो कम्यूनिटीज इग्नोर की गई हैं उन को उस में शामिल किया जाय। जो नहीं हैं उन को एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए काम्प्रीहेंसिव बिल आना चाहिए।

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao) : Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister, Mr. Mandal, took some time and dwelt at length on the reasons to bring forward this Bill. But I do suppose that the reasons which have motivated this Government to bring forward this Bill can be put more briefly and pithily. The main reason to my mind is the same which led the Government to constitute recently the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and not so recently, the Commission on Minorities. Since this Government came into power, there has been an outcry all over the country, there has been a fear in the minds of the Harijans and of the minorities that this Government is the Government of the upper classes, that this Government is the Government particularly of the rural rich and, therefore they are not safe in the hands of this Government. It is not I who is saying so but no less a person than Mr. Jagjiwan Ram, the second senior most Minister in the Janata Party Cabinet, did say it in his now famous speech in Chandigarh more than a year ago. And no less a person than Mr. Chandra Shekhar, President of the ruling party, did say the same thing and voiced the same grievances and the same fears.

I should like to think that merely by bringing forward legislation, merely by throwing a sop to the Harijans the problem will not be solved as it was not solved in the case of the minorities by constituting the Commission on Minorities. This problem cannot be solved by adding cosmetic trimmings to an ugly situation. To my mind, this problem can only be solved if we have the political will, if we have the courage to give a definite bias, a decisive inclination, a strong bias in all Government programmes towards improvement of the general living conditions of the Harijans of their educational conditions, their health conditions and, of their economic conditions.

I should like to take the question of educational conditions first, because we see that the reservations are there but the backlog of non-filled reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes' seats is increasing every year. Today, I read in the newspaper a letter to the editor. The writer was complaining that a man from the Scheduled Castes just walks in and gets a job because the backlog of reservations is there but another man who is not of the Scheduled Castes and who is more qualified than the Scheduled Castes' man, does not get any job. This problem of reservation is there and because seats are not available to them a resentment is growing among the caste Hindus against this reservations.

The problem has to be tackled at its roots. The seats are not being filled because there are not educationally qualified people in sufficient numbers to fill the seats, and one of the most shocking disclosures, so far as the Harijans problem is concerned, is made in all those Government reports which relate to the educational progress of this section of our society. May I refer to a publication of the Ministry of Home Affairs of 1975 entitled "Development of Scheduled Castes—An Appraisal". This tries to bring out the great amount of progress that has been made, but it cannot shut out the actual facts and figures, and it does revel, for instance ....

SHRI SURAJ BHAN : How far is it relevant ?

SHRI EDUARDO FALEIRO: I should not repeat this because I am cutting on my own time, but the point I am trying to make is this that while I welcome this Bill because some sections of our society are going to get some benefit, I am saying don't, think that by bringing for this legislation, you are really giving substantial benefit in solving the problem.

I am now an my second propostion, that you cannot solve the problem unless you give educational facilities and see that these educational facilities are utilised. I am on the point that educational facilities so far have not been utilised and in this context I am referring to the publication of the Home Ministry which is to this effect that in Standards 1 to 5, 62.2 lakhs and 68.33 lakhs students had enrolled respectively in 1968-69 and 1973-74. Then the publication goes on to say that in Standards 6 to 8 their number went down from 62 lakhs to 12 lakhs, and when the students came to standards 11, they were only 5 lakhs of them. The point I am trying to make is the enormous amount of drops-outs among Harijans students as they go on progressing in education which is not good for the system which is a wastage of money, and what is much more important, the opportunity for bringing out the real talent in the Harijans to the forefront is not really being utilised by this community which deserves all protection.

Then, what is happening in the primary and sedondary education is again happening, and much more so, in higher institutions of learning. I am just quoting from the *Economic Political Weekly* for January 28/February 4, which has a very interesting article and a study about the I. I. T. I. Bombay. In the IIT, Bombay, which is a very sophisticated institution of technical learning, there is a reservation of 20 per cent in

[Shri Eduardo Faleiro]

admission for students fron the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The students do come there and out of a fair number of students, hardly any one gets through. What are the reasons for this ? Again I should say that the reason for this is that it is not sufficient to have reservation in the educational system. Tne students of this particular section of the population are basically economically under-privileged, and to a large extent their disabilities flow from their poor economic condition. It is necessary that the provisions relating to free lodging, free food and free allowance for cloting should be strictly implemented and increased. Provision is already there, but a larger provision must be made.

Until recently I have been a college student myself, and I do know how much for a college student good dress does count. A student who comes from a poorer environment, because he cannot dress properly or as well as the other students, creates serious problems. He is isolated, he does not get into the mainstream and develops lack of confidence which will harm him in his future life and future career. The point I would like to make is this, that as far as possible the Harijan students should be admitted to urban schools where they begin to realise that caste does not matter at all, that all are basically the same when they study in the same school.

The problem of educational facilities is rooted in the problem of economic disability. We do find that if students from the Harijan community, the minority communities, the poorer sections drop out, it is because their parents require them to work in the fields and earn some money. Why do the parents require them to do so ? Because they are not able to earn well, because they are not properly paid, because the scheme and legislation concerning fair wages are not being implemented in the rural areas.

The rural rich have been and are today more than ever in collusion with the police and they will not tolerate any grievances, any allegations, any attempt of the Harijans to demand what is due to them. They will put it down cruelly and ruthlessly. We have to break down, we have to cut at the very knot which links in all our rural areas, the police and the rural rich.

These are some points that I have made. Again, I will repeat this that we must go to the root of the problem. Reservation is no solution. What has started as protection to Scheduled Castes ultimately will lead to perpetuation of caste. What is required is the political will and the statesmanship. In the case of the particular Scheduled Castes who have now attained the higher level, they should be de-scheduled, and the other castes which are really poor and which are not in the scheduled list, should be brought in. This requires political courage and this requires statesmanship, but it is necssary if we are really going to achieve the dream which is the dream of all of us, or at least of most of us a truly classless and casteless society

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri) : Mr. Chairman, Sir, I take this opportunity to invite the attention of the hon. Minister of State for Home Affairs to a matter of immense significance to all of us where the question of extending to neo Buddhists the concessions and privileges guaranteed under the Constitution to Scheduled Castes is concerned.

Sir, I have given an amendment, Amendment No. 5. I am, however, aware that that amendment is with reference to Scheduled Tribes. But as I have already said, taking this opportunity I would like to highlight this point as far as the debate on this Bill is concerned.

Sir, the question has remained a burning question ever since their conversion to Buddhism in October, 1956 and as every one of us knows the whole of the State of Maharashtra was afire a few months back and you are also aware that the leaders of the neo Buddhists were on hunger strike here at the Boat Club some months back and many Call Attention notices and other motions were raised in this particular House. And as every one of us knows, all the parties are actually committed to the solution of this particular problem. I feel that the hon. Minister of State for Home Affairs should assure this hon. House as to what would be the policy of his Government on inclusion of these neo Buddhists in this particular schedule of Scheduled Castes. The agitation and movements are still erupting and the whole Buddhist community in this country is put into turmoil, as revealed in the press, practically every day.

I would invite the attention of the hon. Minister to the definition of "Scheduled Castes". I will not read that. It is embodied in Article 366(24) of the Constitution. Then Article 341(1) empowers the President, after consultation with the Governor thereof, to specify by public notification the castes which are to be treated as Scheduled Castes, and Article 341(2) empowers the Parliament to include or exclude from the list of these particular Scheduled Castes. When this question of

inclusion of neo-Buddhists in Scheduled Castes is raised, the usual defences that are raised by the Government are mainly two. Firstly, it is said that Section 3 of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, mentions that no person who professes a religion differe t from Hindu-Sikh religion shall be deemed to be a member of Scheduled Castes and neo-Buddhists being not Hindus, this facility or this advantage cannot be given to this particular community of neo-Buddhists.

The second argument that is advanced against this proposal is that if these facilities are extended to neo-Buddhists, the same will have to be extended to the Scheduled castes people who have embraced other religions such as Christianity or Islam. Now in this connection, I feel that both the arguments that are advanced are fallacious. But before going into the merits of the two arguments, I would like to invite the attention of the hon. Minister to the opinion expressed by Jayaprakashji in December 1977. His statement was published in the papers. I quote :

> "Problems of neo-Buddhists deserved consideration and the Government should give them due attention. Conversion to Buddhism has neither improved their economic condition nor in practice, enhanced their acceptability to caste Hindus. While conversion may have been inspired by the wish to practise an inherently more attractive religion it appears to have been motivated, too, by their despiration at their wretched status as to untouchables and their desire to throw off the humiliating rigours of a system from which there was no escape for them but outright rejection ; surely, it is far from such an action being condemnable it is both courageous and praiseworthy."

Now the only point that we will have to consider is, only because they have converted themselves to Buddhism in the year 1956 and the status and the sufferings are not changed, whether we have to deny to this community the facilities and advantages which were available to them before they converted themselves to neo-Buddhists.

Now in this connection, I would like to invite the attention of the hon. Minister to Article 25 of the Constitution which lays down that the fundamental freedoms guaranteed under the Constitution of India include the freedom of conscience and the freedom to practice any religion of one's choice.

If that right has been guaranteed under the Constitution to every citizen of this country to practice any religion he wants and then unless and until his status and sufferings are changed can we say that only because they have converted to Buddhism, the facilities shall be denied to them?

SHRI K.P. UNNIKRISHNAN (Badagara) : Or Christianity.

SHRI BAPUSAHEB PARULKER : No doubt about it. Not only that, as I said the argument that these neo-Buddhists are not Hindus is prima facie not acceptable to me because if one reads the explanation to Article 25 of the Constitution which lays down that Hindus include Sikhs, Buddhists and all other persons and if we take into consideration all the Acts of the Government of India, viz., Hindu Succession Act, Hindu Marriage Act, Untouchability Act, Protection of Civil Rights Act and Section (3) of this particular Act, which is referred as to as Protection of Civil Rights Act, we find that the word 'Hindu' has been defined as follows :

"Hindu includes a Sikh, a Buddhist and a Jain and other persons". So, when the word 'Hindu' includes neo-Buddhists, I fail to understand the logic in the argument that Section (3) of the Constitution (Scheduled Castes) Order applies to Hindus and therefore, this cannot be made applicable to neo-Buddhists. In my opinion, this arguments does not hold any water. On the same grounds, the argument that if these facilities are extended to neo-Buddhists it will have to be extended to persons who have embraced Islam or Christianity also does not, in my opinion, hold water.

Therefore, I would request the hon. Minister to assure the House after taking into consideration all the submissions I have made ; that all the facilities which these Scheduled Castes people who converted themselves to Buddhism in 1956, were enjoying will be given to them. If that is not possible, I would ask him to give the reasons. as to why the Government feels that these facilities should be denied to them.

The second point, and a small point, is that in entry No. 18 as far as Maharashtra is concerned the word "Gond Rajgond" is tried to be amended by putting a comma after the word 'Gond'.

Therefore, I would like to know—I have moved an amendment—whether, according to the Government, Gond Raj-Gond is a caste or whether Gond Rajgond, Gond and Rajgond are three different castes because, we find, in this particular Schedule, there is Gond Gawari and, if you are going to take Gond and Rajgond

[Shri Bapusaheb Parulkar]

as two different castes, why not apply the same rule to this community, Gond and Gawari. As far as Gawari community and caste is concerned, since 1950, they are making repeated attempts to get this included as Gawari. I would seek that particular clarification from the hon. Minister.

I would request the hon. Minister to give us an assurance on the issue of neo-Buddhists. The remaining points I would submit when I move the amendments.

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर (बम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है, यह पूरे तरीके से विचार कर के नहीं लाया गया है । जैसा कई मेम्बरों ने कहा और मैं भी कहना चाहती हूं कि इस बिल के द्वारा कुछ कम्यूनिटियों को निकाला गया है और दूसरी जगह पर कुछ कम्यूनिटियों को एड किया गया है । गुजरात में बौद्धों को निकाला गया है। लेकिन यह सब कौन-सी कसौटी लगा कर किया गया है, इसका खुलासा मंत्री जी ने नहीं किया है । जिन कम्यूनिटियों को निकाला गया है, उनकी कौन-सी तरक्की हो गयी है, इसके बारे में कुछ लिखा हमारे पास आना चाहिए था वह भी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इन कम्यूनिटियों में कुछ भागों में प्रगतिशीलता आ गयी है लेकिन कौन-से हिस्सों में प्रगतिशीलता आ गई हैं, एजूकेशन में उन में प्रगति हो गई है, उनकी इकोनोमिक कंडीशन अच्छी हो गयी हैं, किस किस तरीके से वे प्रगति कर पाये हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है । खाली उनको निकालने के लिए यह बिल लाने की कोशिश की है । यह एटीच्यूड सरकार का गलत है, ऐसा मैं मानती हूं ।

हमारे देश में अब बहुत सी बड़ी-बड़ी कम्यूनिटियां भी मांग करने लगी हैं कि हम पिछड़े हुए हैं । अभी हमने महाराष्ट्र में देखा, वहां कई कम्यूनिटियों की कांफ्रेंसिज हुई जिनके द्वारा उन्होंने यह मांग रखी कि हम पिछड़े हुए हैं, हमें पिछड़ा हुआ समझा जाना चाहिए और हमें पिछड़ी जातियों के बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिएं । तीस साल की आजादी के बाद भी यह चीज देखने में आ रही है । कई कम्यूनिटियों की महाराष्ट्र में कांफ्रेंसिज हुई और सब ने एक ही मांग की कि हमें पिछड़ा हुआ समझा जाना चाहिए । वे ये सब मांगें इसलिए करते हैं क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को सरकार से सहुलियतें मिलती हैं, अगर वे भी पिछड़ी जातियों में आ जायेंगे तो उन्हें भी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी । अधिक सुविधाओं के लिए वे यह सब मांगे करते हैं । इसके बारे में सरकार को कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए और कोई दूसरी चीज उनके बारे में सोचनी चाहिए ।

शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को जो सहुलियतें आप देते हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि वे पूरी तरह से अमल में नहीं आती हैं । हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटस में कुछ चीजें जानबूझ कर ऐसी की जाती हैं जिनसे उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिएं वे उन्हें नहीं मिल पातीं । अखबारों में एडवरटाइजमेंट्स आते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को नौकरी मिलेगी । अभी अखबार में उनके लिए एडवरटाइजमेंट आया है कि उन्हें नौकरी दी जाएगी । लेकिन अगर आप उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो पायेंगे कि इस तरह की क्वालिफिकेशन रखी गयी है जिस से कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी चुना नहीं जा सके । फिर बाद में यह कहा जा सके कि शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं मिलता है । उसके बाद आपके डिपार्टमेंट में दूसरी जाति का आदमी नौकरी पर रखा जा सके । अभी अभी एडवरटाइजमेंट अखबार में आयी हैं और

उस एडवरटाइजमेंट के बारे में मुझे मालूम है कि किस आदमी को बिठाने के लिए वह एडवरटाइजमेंट लाया गया है। एडवरटाइजमेंट में कहा गया है कि पोस्ट रिजर्व्ड है लेकिन बाद में कह दिया जाएगा कि शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं मिलता है। जो आदमी अभी बैठा है, पूरी क्वालिफिकेशन उसकी उसमें रख दी गयी है। इस तरह से आप देखेंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज को मिलने वाली सहुलियतें उन्हें नहीं मिल पाती हैं। इसलिए मैं आपको वार्निंग देना चाहती हूं कि इस बारे में पूरे हिन्दुस्तान में एक बड़ा धोखा हो रहा है।

इस वजह से यह सब हो रहा है। आप कहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन अमल में उसको नहीं लाते हैं। इस वास्ते मांग होती रहती है कि हम को लिस्ट में शामिल करो। अभी डा० पुरुलेकर ने एक संशोधन रखा है और मांग की है कि नव बौधों को भी ये सब अधिकार मिलने चाहियें, उनको भी जो इन लोगों को सुविधायें मिलती हैं मिलनी चाहियें। आपने देखा होगा कि लीडर चाहे किसी भी पार्टी में हों जब नव बौध उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि वे शेड्यूल्ड कास्ट के हैं तो वे मान जाते हैं और फार्म पर हस्ताक्षर कर देते हैं, खुद लिख देते हैं तो मैं समझती हूं कि यह उचित ही होगा कि जो सुविधायें शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज को मिलती हैं वे उनको भी मिलें। नव बौधों का सब से गम्भीर सवाल महाराष्ट्र का है। बाबा साहेब डा० अम्बेदकर नव बौध बने थे और उनके पीछे चल कर, उनका अनुकरण करते हुए बहुत से माहर कम्यूनिटी के लोग महाराष्ट्र में नव बौध बन गए थे। लेकिन उन की स्थिति वैसी की वैसी है, उस में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इकोनोमिक कंडीशन उनकी बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी। सामाजिक स्तर पर उन्होंने धर्म बदल लिया है लेकिन उनके लिए पानी की सुविधा तक आज भी उपलब्ध नहीं है। देहातों में उनका बायकाट किया जाता है, उनको कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है। आज भी उनको माहर ही देहातों में कहा जाता है, न्यू बुधिस्ट नहीं कहा जाता है, इस नाम से कोई उनको पुकारता नहीं है। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है लेकिन उनकी आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज की लिस्ट में न्यो बुधिस्ट्स को शामिल करने के बारे में डा० पुरुलेकर का जो संशोधन है उसको आपको स्वीकार कर लेना चाहिये।

शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज को आप जो सुविधायें देते हैं इसको ले कर आप देख ही रहे हैं कि पूरे भारत में एक बड़ी हलचल मची हुई है। आपने निस्सन्देह इनको सुविधायें दी हैं लेकिन जनता के मन में इन लोगों के प्रति कोई परिवर्तन आ गया है ऐसा दिखाई नहीं देता है। अभी की घटना है जो आप देख ही रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिए जाने के कारण मराठवाड़ा में क्या हो रहा है, इसको आप अपनी आंखों से देख ही रहेहैं। सहूलियतें देने से या किसी का नाम सूची में रख देने से या किसी का नाम निकाल देने से जो मूल समस्या है वह हल नहीं होगी। हमें पूरी सोसाइटी में चेंज लाना होगा। अब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक यह जो लिस्ट है यह बढ़ती ही जाएगी। इसके सिवाय और कुछ भी इसका लाभ नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि बेसिकली जहां से उनका जीवन शुरू होता है उस स्तर पर उन सब को आप सहूलियतें देना शुरू करो। बाद में जा कर आपने एक दो प्रतिशत अधिक सहूलियतें उनको दे दीं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह से आप इस समस्या पर विचार करेंगे तो लिस्ट अच्छे तरीके से आप पूरी कर लेंगे। ऐसा आपने नहीं किया और सोन कोली रखा तो बाकी सब कोली कहेंगे कि हम सोन कोली हैं हम को भी शामिल किया जाए ताकि

[श्रीमती अहिल्या पी० रांगनकर]

हमें भी ये सुविधायें उपलब्ध हो सकें। खाली लिस्ट बदलने से कोई सुधार नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि एक कमेटी आप रखें जो पूरे तौर पर जितनी शड्यूल्ड कास्ट्स की समस्यायें हैं, लैंड प्रोबलैम है, इकानोमिक प्राबलैम है, प्रोमोशन का सवाल है, नौकरियों का सवाल है, इन सब सवालों पर गहराई से विचार करके पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दे। जब तक पूरे स्ट्रक्चर को नहीं बदला जाएगा तब तक किसी को शामिल कर देने से या किसी को निकाल देने से कुछ फायदा नहीं होगा, यही मेरा कहना है।

डा० बलदेव प्रकाश (अमृतसर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि बहुत छोटी सी बात को ले कर इस बिल को पेश किया गया है। मैं कहना चाहता हूं क्यों नहीं एक व्यापक बिल पेश किया गया जिस में सभी संशोधनों का समावेश होता? भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो जो संशोधन इस समय आवश्यक हैं उनको ले कर एक व्यापक बिल क्यों नहीं पेश किया गया? हाउस में अब इस छोटे से बिल को ले कर बहस होगी और फिर जब बड़ा बिल आएगा सभी संशोधनों को लेकर फिर उस पर भी बहस होगी और इस तरह से दो बार हाउस का समय लगेगा। इस बिल पर पचास से अधिक संशोधन माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं। और मैंने सभी संशोधन देखे हैं, मंत्री महोदय ने भी देखे होंगे, सभी इसी प्रकार के हैं कि फलां प्रदेश में फला फलां जातियों, उपजातियों को अनुसूचित जाति की सूची में रखा जाय। अगर इतनी समस्यायें हमारे सामने हैं कि हर प्रदेश में किसी न किसी जाति को इस सूची में रखना चाहिये या न रखना चाहिये, तो क्या यह सरकार के लिये आवश्यक नहीं हो जाता की सभी प्रदेशों से एक एक व्यक्ति को रख कर के इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजें जिससे वहां अच्छी तरह विचार हो और यह समस्या हमेशा के लिये समाप्त हो सके। मंत्री महोदय ने कहा कि गुजरात में क्योंकि सारे प्रदेश के लिये मोची अनुसूचित जाति में रखे गये इसलिये वहां पर आन्दोलन हुआ और उस आन्दोलन के दृष्टि गत सरकार सारे प्रदेश से हटा कर एक जिले के लिये प्रबन्ध कर रही है। ऐसी ही सिफारिशें बाकी प्रदेशों से भी सरकार को आयी हैं। पंजाब प्रदेश से पिछले दो, तीन साल से धोबी बिरादरी अनुसूचित जाति में रखी जाय सरकार की तरफ से वह सिफारिश केन्द्र को आयी है और वहां पर इस समस्या को ले कर के कई प्रकार के आन्दोलन हुए, मीटिंगें हुई, सरकार को मेमोरेन्डम दिये गये और सरकार ने यह मांग यहां पर भेजी। सारे देश में धोबी अनुसूचित जाति हैं, लेकिन पंजाब में नहीं है। दिल्ली में रहने वाला एक भाई अनुसूचित जाति में है, लेकिन पंजाब में रहने वाला दूसरा भाई नहीं है। उसको सभी सहूलियतें प्राप्त हैं, लेकिन दूसरे भाई को जो पंजाब में रहता है वह सहूलियतें प्राप्त नहीं हैं। हरियाणा, हिमाचल के अन्दर है, पंजाब के अन्दर नहीं है। तो यह समस्यायें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इसलिये मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि इसको पास कराने की जल्दीबाजी न करें और बहुत जल्दी एक व्यापक बिल, जिसमें अनुसूचित जातियों की सभी समस्याओं का ठीक वर्गीकरण हो सके, वह सदन के सामने प्रस्तुत करें। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*SHRI A.V.P. ASAITHAMBI (Madras North) : Mr. Chairman, Sir, through this Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill the Government seeks to restore the position in respect of the Mochi community in the list of Scheduled Castes of Gujarat State which obtained prior to the enforcement of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Act, 1976, and certain mistakes of spellings and punctuations committed by the careless officials in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders

*The original speech was delivered in Tamil.

(Amendment) Act, 1976, are also proposed to be corrected. Many hon. Members of this House have proposed several amendments to this short Bill. They want to include certain communities and castes in their regions to be included in the SC and ST list. As the hon. Member who preceded me pointed out, the Government should have taken this opportunity for bringing a comprehensive Bill incorporating all the communities and castes which the hon. Members want to be included in the list.

I want to know whether the Minister has been prompted to introduce this Bill just because the Prime Minister hails from Gujarat. Only in 1976 the Mochi community was included as a scheduled caste in the list. Within two years this amending legislation has been brought in for treating them as scheduled caste in adistrict or in just two taluks and this community has become an advanced community in other parts of Gujarat. Is it the aim of the Janata Government to undo everything that has been done by the former Government? The hon. Minister of State of Home Affairs in his introductory speech referred to the necessity of introducing this Bill because of the agitation of certain sections in Gujarat. Supposing there is again agitation after the enactment of this Bill, what will the Government do? The Government should not be afraid of agitation for just causes. Similarly, it is also the duty of the Government to suppress agitations for wrong causes.

It is not proper to exclude one community after treating it as a scheduled caste. How can this community continue to be scheduled caste in one part of the State and in other parts an affluent one? We have reserved constituencies for the scheduled castes. A citizen of India, according to our Constitution, can contest for any elective office anywhere in India. I would like to ask: can a representative of Mochi community contest for an elective office from Delhi. If Mochi community has been included in the list of Scheduled Castes in Gujarat, it should be treated as scheduled caste throughout the country. It should not be—it is constitutionally improper and morally wrong—to say that Mochi community is scheduled caste in one part—that too in one or two taluks—and not so in other parts. A few people belonging to this community might have become rich and it does not mean that the entire community has become affluent to be excluded from the list of scheduled caste list.

17 hrs.

I would go to the extent of saying that there should be no difficulty in including communities in the list of Scheduled Castes. Whoever is a *sudra* is a scheduled caste man. Many communities which are to find a place in the list have not been included so far. For example, the Dhobis, barbers, fishermen etc. in Tamil Nadu do not find a place in this list. They should be included in this List.

Here I would refer to another anomaly in the policy of the Government. The scheduled caste people who became Buddhists or Christians are denied the amenities and facilities for their development. It must be analysed why they change their religion of birth. If they continue to remain as Hindus, they will be for their life sudras, untouchables and down-trodden to be dominated by the caste-Hindus. That is why Dr. Ambedkar advocated the cause of conversion of Scheduled Castes. Periyar Ramaswamy in Tamil Nadu pleaded for their religious conversion so that their postrity can be free from oppression and domination by caste-Hindus. We should not deny the concessions, amenities and facilities to the Buddhist and Christian converts of Scheduled caste communities. It is necessary to transform our attitude and approach before we condemn their religious transformation. I am a pucca Hindu. Asaithambi can become in a jiffy Abdul Khader. Asaithambi can change his name to Stephen and become a Christian. Can a Muslim or a Christian become a Hindu easily? Even if he becomes a Hindu, to which community he would belong? Which community will embrace a Muslim convert or a Hindu convert as its own? Hindu society is caste-ridden. I would warn that the bane of Hindu society is its caste distinctions. It should be the constant and conscious endeavours of the Government to raise the Scheduled Castes and Scheduled Tribes economically and educationally so that they become an inalienable part of the main-stream of our country. Then only the shackles of casteism and the chains of slavery can be cut as under in this country of ours.

I understand that Mochi community is engaged in manufacturing and repairing chapps, shoes etc. It cannot be that they have become rich in all parts of Gujarat except in two Taluks where they continue to be scheduled caste. The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes must engage himself in a comprehensive study in depth to find out what other communities in the country are to be brought in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The upliftment of the downtrodden should be the cornerstone of all legislative efforts of the Government and not tinkering with a legislation

[Shri A. V. P. Asaithambi]

here and there. Before I conclude I demand that the officials responsible for the mistakes in spellings, punctuation etc. must be taken to task, if such lapses have led to the loss of concessions to any particular Scheduled Caste Community.

SHRI PURNANARAYAN SINHA (Tezpur): Sir, I have got an amendment already tabled. I want to speak.

MR. CHAIRMAN: What do you want?

SHRI PURNANARAYAN SINHA: When you called me, I was in the Business Advisory Committee meeting. I want to speak on this.

MR. CHAIRMAN: Anyway, we shall see.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि "शिड्यूल्ड कास्ट्स" शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं। जिस समय शिड्यूल्ड कास्ट्स का सृजन किया गया था, उस समय शिड्यूल्ड कास्ट्स को डेफ़ाइन किया गया था और उस में डिप्रेस्ड क्लासिज, एक्सटीरियर क्लासिज, एक्सक्लूडिड क्लासिज और बैकवर्ड क्लासिज को इनक्लूड किया गया था।

इस बारे में इंडियन लेजिस्लेटिव कौंसिल में 1916 में डिसकशन हुआ था और वहां यह निर्णय किया गया था कि डिप्रेस्ड क्लासिज में इन को इनक्लूड किया जाये : (1) क्रिमिनल एंड वांडरिंग ट्राइब्ज, (2) एबोरिजिनल ट्राइब्ज और (3) अनटचेबल्ज।

1917 में भारत सरकार के एजूकेशनल कमिश्नर, सर हेनरी शार्प, ने डिप्रेस्ड क्लासिज की एक लिस्ट तैयार की, जिस में उन्होंने इन को इनक्लूड किया : (1) एबोरिजिनल या हिल ट्राइब्ज, (2) डिप्रेस्ड क्लासिज और (3) क्रिमिनल ट्राइब्ज। इस बारे में उन्होंने कहा था :

"The depressed classes from the unclean castes whose touch or even shadow is pollution."

साउथबोरो कमेटी, 1919, स्टेचूटरी कमीशन और इंडियन सैंट्रल कमेटी ने डिप्रेस्ड क्लासिज में शामिल करने के लिए केवल अनटचेबिलिटी के सिद्धांत को ही स्वीकार किया। इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी ने कहा :

"The term Depressed Classes should not exclude primitive or aboriginal tribes, nor should it exclude those Hindus who are only economically poor and in other ways backward but are not regarded as untouchables."

लेकिन डा० अम्बेडकर ने कहा कि डिप्रेस्ड क्लासिज के स्थान पर एक्सटीरियर क्लासिज या एक्सक्लूडिड क्लासिज जैसा कोई नाम होना चाहिए। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं कि मंत्री महोदय के विधेयक का मुख्य मुद्दा यह है कि किस कास्ट को शिड्यूल्ड कास्ट्स में रखा जाये और किस को न रखा जाये।

1931 की सैन्सस में इस बात के लिए पांच मापदंड निश्चित किये गये कि किस को अछूत माना जाये : (1) जो ब्राह्मण के यहां सेवा नहीं कर सकता है (2) जिस का काम नाई, धोबी, दर्जी आदि नहीं कर सकता है, (3) जो सार्वजनिक कुंए और सड़क आदि को व्यवहार में नहीं ला सकता है, (4) जिस के लिए मंदिर में प्रवेश निषिद्ध हो, और (5) जो सामाजिक रूप से अछूत है।

इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947 में कहा गया है :

"The "Scheduled Castes" means such castes, races of tribes or parts or groups within castes, races or tribes, being castes, races, tribes, parts or groups which appear to the Governor-General to correspond to the classes of persons formerly known as the "Depressed Classes" as the Governor-General may by order specify."

After Independence, the term "Scheduled Caste" is used in the Constitution to specify the untouchables.

341(1) में इस प्रकार है —

"The President may with respect to any State or Union Territory, and where it is a State after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes, which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State or Union Territory, as the case may be."

उसकी दूसरी धारा में कहते हैं—

"Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification."

इस के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं उन को पढ़ कर आप का समय नहीं लेना चाहता हूं। मंत्री महोदय वकील रहे हैं, उनको सारी चीजों का ज्ञान हैं। जो शेडयूल्ड कास्ट्स के सम्बन्ध में बहुत सारी भावनायें हैं, वे मैंने रखी हैं कि अछूत कौन है। इस के सम्बन्ध में एक जगह ऐसा आया है—मैं अभी देख रहा था—कांस्टीचूशन का ही एक भाग था, उस में कहा गया ह, जब आर्यों ने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की तो जिस ने उन को आधीनता को मान लिया; उस को कहा कि इस को सब काम दो और जिस ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, उन को कह दिया गया कि तुम अछूत हो। मतलब कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं, वे यहां के मूल निवासी हैं।

दूसरी थ्योरी यह है —

"The untouchables were secluded because they were outside the scheme of creation. This is the reason why they were termed as Antyajas."

लेकिन डा० अम्बेदकर ने कहा कि अन्त्यज का मतलब है कि जिस का घर गांव के किनारे हो। आज भी आप जा कर देख, तो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन के घर गांव के किनारे पर पायेंगे मनु स्मृति के मुताबिक उन के घर इस लिये गांव के किनारे रखे गये हैं, जिस में उस की हवा गांव में प्रवेश न करे।

यह सारी चीजें हैं और इन के आधार पर अनुसूचित जाति का क्रियेशन किया गया। महात्मा गांधी ने इन का नाम हरिजन रखा, लेकिन आजादी के तीस साल के बाद भी जो हरिजनों की दुर्दशा है, वह हम को और आप को, सब को मालूम है। उस में भी वही लोग आज कुछ तरक्की कर पाये हैं जो इकानामिक दृष्टिकोण से डेवेलप्ड हैं। आज हम जितने पार्लियामेन्ट के सदस्य हैं उन के आंकड़े ले लीजिये, वे वही हैं जिन के पास खाने भर का अनाज है और जिन के पास कुछ बुद्धि है। लेकिन आज जो आप के यहां नौकरी कर रहा है; अनुसूचित जाति का सदस्य उस का कहीं भी भविष्य नहीं है। हम को आश्चर्य होता है हमारे साथी ने ठीक ही कहा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, क्या कारण है कि मैं पासवान हूं और दिल्ली का पासवान हमारे पास आ कर कहता है कि हम 16 साल से यहां दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन हमारी गिनती अनुसूचित जाति में नहीं है। मंत्री महोदय के पास हम ने दो-दो बार पत्र लिखे; पार्लियामेन्ट में क्वेश्चन पूछा, लेकिन मंत्री महोदय ने 1921 का, या कब का, पता नहीं कौन-कौन सा रूल पढ़ दिया दिल्ली का, कि यह रूल है कि 21 साल के अन्दर के जो लोग रहगे उन को अनुसूचित जाति में नहीं माना जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार में अनुसूचित जाति की जो लिस्ट है, जिस के सदस्य सिर्फ बिहार में ही है, दिल्ली में नहीं हैं वे अगर बिहार से दिल्ली में नौकरी करने के लिये आते हैं, आप उन को रोजगार नहीं दे पाते हैं, अपना पेट पालने के लिये दिल्ली आते हैं, तो उन को आप ने कह दिया कि तुम अनुसूचित

[श्री राम विलास पासवान]

जाति के नहीं हो, इस से ज्यादा घोर शमनाक चीज और क्या हो सकती हैं मंत्री महोदय को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है । इस लिये आप सर्वप्रथम तो एक बात कर दें शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग जहां भी हैं वे देश के किसी भी कोने में जाये, तो वे शेड्यूल्ड कास्ट्स में रहें । यह तो सब से पहली चीज है । यहां दिल्ली में हम लोगों के पास प्रति दिन तमाम लोग सर्टिफिकेट के लिए आते हैं । आपने तीस हजारी कोर्ट में आफिस कायम किया हुआ हैं जहां से 6–6 महीने तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है । वहां जो अफसर बैठे हुए हैं उनका काम क्या है कि वे देखें कि यह 25 साल से है या नहीं । तो इस नियम को आप तुरन्त खत्म कर दें ।

दूसरी बात यह है कि अभी हमारे साथियों ने कहा कि यह छोटा सा बिल है इसको बाद में लाना चाहिए था, मैं कहता हूं मुझे खुशी है क्योंकि यह तो सेलेक्ट कमेटी में जायेगा और मन्त्री महोदय हमारी भावनाओं से परिचित होंगे । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप एक फार्मूला बनायें और जैसा उन्होंने कहा, आप निकालने की बात छोड़ दीजिए । प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं, सब से बड़ा धब्बा प्रधान मंत्री जी पर लगा क्योंकि गुजरात से हरिजनों को हटाया जा रहा है। वहीं से यह हुआ है । इसलिए आप हरिजनों को हटाने की बात मत कीजिए । आप हरिजनों को जोड़ने की बात कीजिए। आप देखें कि कौन लोग एकोनामिकली सामाजिक दृष्टिकोण से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से गिरे हुए हैं । इन तीनों दृष्टिकोणों से जो गिरे हुए है उनकी आप सूची बनायें और उनको इनक्लूड किया जाये । जो यह कहा जाता है कि अनुसूचित जाति के लोगों को इससे हानि होगी तो ऐसी बात नहीं है । आज आप 14 परसेंट रिजर्वेशन दे रहे हैं जबकि हमारी संख्या 20 प्रतिशत है । अगर आप उनको भी इनक्लूड कर देंगे तो वह 30 परसेंट हो जायेंगे और फिर हम 30 परसेन्ट की मांग करेंगे और पापुलेशन के अनुपात में आरक्षण आपको देना होगा । इसलिए इसमें हमारा कोई घाटा नहीं है। आप एक व्यापक नीति बनाकर जो लोग सोशली, एकोनामिकली और एजूकेशनली गिरे हुए हैं उनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित करें । इसको आप सेलेक्ट कमेटी में भेजें और दोबारा बढ़िया तरीके से बिल बनाकर लायें । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

SHRI G. S. REDDI (Miryalguda) : Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Members to the speeches made by Mr. Parulekar and Smt. Ahilya Rangnekar, who said that because of their conversion to Buddhism, people do not become less-depressed. They are belonging to the same Scheduled Caste origin; therefore, they should get all the benefits which the Hindus get. Under our Constitution, we have got the Scheduled Castes Order of 1950, which has included a clause, namely, Clause 3. It says that those who do not profess 'Hinduism' are not scheduled castes. But later on we added the Sikh Community also along with the Hindus.

Therefore, Sir, now, as things stand today, those belonging to Hinduism and Sikhism alone are called Scheduled Castes. Not others. Now the question is whether those belonging to Buddhism or Christianity or Islam are to be deprived of the benfits, inspite of the fact that they are scheduled castes and they suffer from all the disabilities which the Hindu Harijans suffer from. This is the question.

This Clause, Clause No. 3, of the Scheduled Caste Order of 1950, I say, is a discriminatory clause. The discrimination is based on religion. Those who profess Islamic religion, or Buddhism or Christianity are discriminated against.

Sir, should we say that in this country of ours, where we preach and practice secularism, discrimination should be based on religion and religion alone?

Now, those Scheduled Caste people who have converted themselves to Chistianity are subjected to the same type of untouchability and the same type of caste discrimination in our villages—leave alone those few Christians whom you may see in the towns. We see all this in the case of people of other religions also. They are scheduled castes though they may come to the towns and they may appear as advanced classes. Therefore, I would appeal to the Hon. Minister to appoint Committee so that it can go into this problem and also examine whether these peopleafter their conversion to Islam, Buddhism or Christianity are not discriminated in the villages. They are discriminated and untouchability is rampant in the villages. Now because they are convereted to Christianity or Buddhism or Islam, you should not consider them that they are advanced. It is very bad to consider that those who belong to above religions should not be given these facilities. Now, in our country, we take pride that we are secular country and we should see that secularism is practised in our country.

Now, tihs is a very daring clause, that is, clause 3 of the Scheduled Caste Order, 1950, where religion is taken as the basis. Now, some of you may argue that there is no casteism in Christianity or in Islam or in Buddhism. If you go to the villages and examine the present situation , you would find that casteism is still practised. Now, because they have converted themselves into other religions, untouchability has not disappeared or diminished. It is there and it isvery much rampant. Therefore, I appeal to the hon. Minister to see that we do not practice any kind of discrimination based on religion.

Now, if our basisis economic backwardness, we have not quarrel. Whether he belongs to Brahmin Caste or Reddi caste or any other caste, if it is merely a question of economic backwardness, nobody has any quarrel. But the whole basis of Scheduled Caste Order, 1950, is based on religious discrimination. This religious discrimination is so rampant that all those belonging to Buddhism, Christianity or Muslim Religions are suffering under this. Now, we want that socially backward and down-trodden people should be given help. It should be the policy of the Government of India to see that these people are uplifted. It is a very good policy, but that should not be based on religion. I can quote an example. Today, if a person named Paul who is a Christian, i s denied all those benefits, tomorrow if he becomes 'Gopal', Government will offer him all the facilities.

SHRI A.V.P. ASAITHAMBI : Gopal can become Paul but Paul cannot become Gopal.

SHRI G.S. REDDI : A person called Mr. Paul, who is considered to be belonging to an advanced community in our country is denied all benefits but tomorrow if he converts himself to Hinduism as 'Gopal' he has all the benefits. If a person named Mr. Paul brings a certificate that he has converted himself to Hinduism and called himself 'Gopal', he is given all the benefits. Now what more example you want to show that the discrimination is based on religion? Therefore, while the Government of India helps all the downtrodden people, all the poor people and backward class people, they should help these people also. Now, some of us feel that by giving help to Christians, Muslims and Buddhists, it will cut away the slice of the benefits given to the Hindu Scheduled Caste people. It is wrong to think so. But more funds should be set apart for this purpose rather than cutting away the grant. Now, when the Government of India considers these people as downtrodden who are scheduled castes and threat them in an equal way, they should not discriminate against them on the basis of religion. Here I would like to give an example. Mr. Charan Singh in his book has mentioned "you can change religion but you cannot change the caste. Our Indian Society is caste-ridden. We are divided into castes". Therefore our basis of help should be on economic backwardness and not on caste basis or on the basis of religion.

This Bills provides for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of scheduled castes and scheduled tribes of certain castes and tribes. These inclusions should be made. Several hon. Member have sent their amendments to the effect that the converts from the scheduled castes and scheduled tribes t o other religions should also be included in this list. This should be accepted by the hon. Minister so that equal justice is done to them and there is no discrimination on the basis of religion.

श्री कचरु लाल हेमराज जैन : (बालाघाट) : सभापति महोदय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब से यह सत्र चालू हुआ है, 17 तारीख से, इस सदन में केवल एक ही चर्चा चल रही है और वह है कुर्सी-दौड़ की और इस बिल को पेश कर के माननीय गृह राज्य मंत्री ने यह काम किया है कि वैसे तो वे चिंतित हैं कि चारों तरफ देश में शान्ति भंग न हो और वह बनी रहे लेकिन इस बिल के द्वारा वे ऐसा ही काम कर रहे हैं जैसे जले

[श्री कचरू लाल हेमराज जैन]

पर नमक छिड़कना और अग्नि में घी डालना ।

सभापति महोदय, कल जब इस बिल के बारे में सारी जनता के सामने अखबारों में बातें आएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि इन की क्या परिस्थिति बनेगी । मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता । मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते हुए यह कहा कि यह तो एक साधारण सा और छोटा सा बिल है । 1974 में गुजरात में श्री जय प्रकाश नारायण जी ने एक नारा दिया था और उस से इस देश में एक नई क्रान्ति आई जिस के कारण यह नई सरकार बनी और आप मंत्री बने । इस तरह का बिल ला कर गुजरात में एक आग भड़केगी और वह एक ज्वालामुखी के समान होगी और उससे आप भस्म होने से नहीं बच पायेंगे । क्या आप यह समझ रहे हैं कि यह एक साधारण सी बात है । आपको मालूम होना चाहिए कि यह एक साधारण सी घटना एक बड़ा स्वरूप ले सकती है । मैं इस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहता लेकिन मेरा आप से यह निवेदन है कि माननीय सदस्यों ने जो आप को संशोधन दिये हैं, उन को आप मानें । मैं आप को एक चेतावनी देना चाहता हूं । मैंने यहां पर 22 फरवरी को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित बनारस कांड पर एक स्पीच दी थी और याद दिलाया था कि बाबू जगजीवन राम का अपमान करने के लिए जो शर्मनाक घटना घटी थी, उस के लिए चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना चाहिए । आज स्थिति तनावपूर्ण है और इस विषय को ले कर पुनः इस देश में ज्वाला भड़केगी । नव-बौद्धों के बारे में आज हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आन्दोलन सारे देश में चल रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई भागों में यह आन्दोलन चल रहा है । इसलिए इस बात को आप साधारण बात मत समझिये । आज मोची समाज की बात कही जा रही है । गुजरात में गोड़ गोआरी समाज है, उन के बारे में कुछ करना चाहिए । चारों तरफ आज देश में अशान्ति फैली हुई है और इस विधेयक को ले कर देश के अन्दर एक विस्फोट हो सकता है । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसे आप वापस ले और विस्तृत तैयारी कर के और सभी तरीके से अच्छे ढंग से बड़े रूप में आप इस को लाएं । यह साधारण विषय नहीं है । पिछली सरकार ने इस विषय को इतना पेचीदा बना दिया है कि आज करोड़ों लोग इस के अन्तर्गत आने वाले करोड़ों लोग, बड़े गुमराह हो रहे हैं और सारे देश के अन्दर इस बारे में भ्रान्ति फैल रही है । इस भ्रान्ति को मिटाने के लिए, मेरा निवेदन है कि आप एक विस्तृत विधेयक लाएं । हम लोगों के बीच में रहते हैं और उन्हीं के द्वारा हम इस पार्लियामेंट में आए हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन के हृदय में क्या है, हम उन के हृदय की आवाज को जानते हैं । वे बाहर क्या कह रहे हैं, यह हमें मालूम है और आप ने कह दिया कि यह छोटी सी बात है । इस पार्लियामेंट के भवन में यह छोटी सी बात दीखती हो लेकिन अगर आप बाहर देखें तो आप को पता चलेगा कि लोगों के दिलों में ज्वाला भभक रही है और वह आप की इस टीपी और चोटी को नहीं रहने देगी । इसलिए मेरा कहना यह है कि इस विधेयक के साधारण स्वरूप को न देखते हुए, पूरे तरीके से इस पर आप को विचार करना चाहिए । यहां पर कई लोगों ने गोंड जोआरी के बारे में कहा । ये लोग आप के यहां बर्तन मांजते हैं और आप की बीवियों के कपड़े धोते चले आ रहे हैं । तीस साल से वे लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें भी

इन जातियों में जोड़ा जाए : वे लोग हमारी गऊएं चराते हैं, हमारे घरों के बर्तन मांजते हैं। न पिछली सरकार ने उन की बात सुनी और न आप सुन रहे हैं। आप ने भी उन के लिए इसमें कुछ नहीं किया। वह गौंड गुआरी जाति आपकी गऊएं चराती हैं, आपके घरों के बर्तन मांजती है। उस जाति को इसमें नहीं जोड़ा गया है। यह कोई साधारण सवाल नहीं है, यह एक बड़ा विस्तृत सवाल है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि यदि आप इस जाति को इसमें नहीं जोड़ते हैं तो आपको कौन बहुमत देगा, कौन आपका साथ देगा यह बात मेरी समझ से परे है। हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा कर शकल दिखानी पड़ती है और लोगों से मिलना पड़ता है। हम वहां जा कर क्या कहेंगे और कौन हमें और आपको इस सदन में आने के लिए बहुमत देगा। इतना ही मैं कहना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN : We shall now take up Half-an-Hour discussion.

17.31 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

PENSION TO HEIRS OF DECEASED MISA AND DIR DETENUS

SHRI R.K. MHALGI (Thana) : Sir, thousands of patriotic sons and daughters of the motherland participated in the "People's Great Struggle" against the Emergency. Participation in the satyagraha and the underground resistance movement earned for them detention under MISA or imprisonment under DIR. As a result they were subjected to untold sufferings and economic ruin.

As many as hundred and more have embraced death during detention. Hundreds have become physically unfit and invalid. Many more are still under medical treatment because of the ill-treatment and continuous beating in jails. The former Government under Indira Gandhi was more barbarous than the British rule. But now a new era has been ushered. Detenus and satyagrahis under Emergency, therefore, deserve all sympathy and assistance.

Sir, the subject under discussion is sentimental and sensitive. Government should therefore, come out with concrete proposals. It is true that Government have announced some of its schemes. But they are insufficient and fall short, to meet the hard requirements of every-day life.

For that purpose, Sir, I categorize the jail sufferers during Emergency in three groups:

(1) Those who died in jails in detention or on parole or during the period of 3 months immediately after their release and also those who died in the underground movement, against whom the warrant of arrest was issued.

(2) Those who have become physically unfit or invalid, partially or in full.

(3) Those who are subjected to economic ruin.

As regards he first category, firstly, out of 74 MISA detenu deaths, according to Government, only for 63 recommendations have been received by Union Government. Have the State Governments assigned any reasons for the delay in the case of the remaining 11 cases? If yes, please give the same, State-wise. Secondly, rejection of as many as 20 application for pension, out of these 63 is undoubtedly a large number. Please give the reasons for each case, in the case of all those 20 rejected recommendations. May I also know whether under the new scheme formulated on 7-7-1978, detenus under DIR would get pension retrospectively *i.e.* from 1-5-1977 when the first scheme came into being

Thirdly, the word dependant is circumscribed by various conditions. They must be relaxed to a reasonable limit. Sir, how it has been presumed by the Government that the sone of the deceased, if he attains the age of 21, becomes economically independant? Whether the Government expects the fatherless boy to relinquish his education and get a job and that too who is going to provide it to him in these hard days of unemployment? Unless the said son economically becomes independant upto the age of 25, he must be provided the benefit of the Scheme.

It may be true that there would not be any one dependant economically upon